



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 250]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 10 जून 2021—ज्येष्ठ 20, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 जून 2021

क्र.-एफ-ए-3-07-2021-1-पांच(26).- राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत के कई हिस्सों में महामारी कोविड-19 के चलते यह अधिसूचित करती हैं कि :-

- (i) जहां, किसी भी प्राधिकरण द्वारा यह किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी कार्यवाही को पूरा करने या उसके अनुपालन के लिए किसी भी समय-सीमा को, जो अप्रैल, 2021 के 15वें दिन से मई, 2021 के 30वें दिन तक की अवधि के दौरान आता है, उक्त अधिनियम के तहत निर्दिष्ट या निर्धारित या अधिसूचित किया गया है, और जहां ऐसी कार्यवाही को पूरी करना या उसका अनुपालन ऐसे समय के भीतर नहीं की गई है, तो, निम्न उद्देश्यों सहित के लिए ऐसी कार्यवाही के पूरा करने की या अनुपालन के लिए समय-सीमा मई, 2021 के 31वें दिन तक बढ़ा दी जाएगी :-
- (क) उपर्युक्त अधिनियमों के प्रावधानों के अधीन किसी भी प्राधिकरण, आयोग या न्यायाधिकरण द्वारा, किसी कार्यवाही को पूरी करना, किसी भी आदेश पारित करने किसी नोटिस को जारी करना, सूचना, अधिसूचना, संस्वीकृति या अनुमोदन या इस तरह की अन्य कार्यवाही जो भी नाम से होय या
- (ख) उपर्युक्त अधिनियमों के प्रावधानों के तहत, कोई अपील दाखिल करना, कोई भी रिपोर्ट, दस्तावेज, विवरणनी, बयान, या ऐसे अन्य रिकॉर्ड को प्रस्तुत करना, जो भी नाम से पुकारा जाता है.

लेकिन समय का ऐसा विस्तार उक्त अधिनियम के निम्न प्रावधानों के अनुपालन के लिए लागू नहीं होगा, जैसा कि नीचे वर्णित है,-

- (क) अध्याय IV;
- (ख) धारा 10 की उपधारा (3), धारा 25, 27, 31, 37, 47, 50, 69, 90, 122, 129;
- (ग) धारा 39, परंतु उपधारा (3), (4) और (5) को छोड़कर;
- (घ) धारा 68, जहां तक ई-वे बिल का संबंध है; तथा
- (ङ) ऊपर वर्णित अध्याय और धारा के तहत बनाए गए नियम;

परन्तु, जहां मध्यप्रदेश वस्तु और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 9 के तहत निर्दिष्ट या निर्धारित या अधिसूचित किसी भी प्राधिकरण द्वारा किसी भी कार्यवाही को पूरा करने की कोई समय-सीमा, जो मई 2021 के पहले दिन से मई, 2021 के इकत्तीसवें दिन तक की अवधि के दौरान आती है, और जहां ऐसी कार्यवाही ऐसे समय के भीतर पूरी नहीं की गई है, तो, ऐसी कार्यवाही के पूरा करने की समय-सीमा जून 2021 के पन्द्रहवां दिन तक विस्तार किया जाता है।

- (ii) ऐसे मामलों में जहां रिफण्ड के दावे को पूर्ण या भाग में, अस्वीकार करने के लिए नोटिस जारी किया गया है, और जहां आदेश जारी करने की समय-सीमा धारा 54 की उप-धारा (7) के साथ पठित उप-धारा (5) के प्रावधानों के संदर्भ में अप्रैल, 2021 के पंद्रहवें दिन से मई 2021 के तीसवें दिन तक की अवधि के दौरान आती है, ऐसे मामलों में, उक्त आदेश को जारी करने की समय-सीमा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से नोटिस का जवाब प्राप्ति के पंद्रह दिन बाद या मई 2021 के इकत्तीसवें दिन, जो भी बाद का हो, तक बढ़ा दिया जाता है।

2. यह अधिसूचना अप्रैल 2021 के 15वें दिन से प्रवृत्त हुई मानी जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 10 जून 2021

क्र. एफ-ए-3-07-2021-1-पांच(26).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 3 के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-07-2021-1-पांच(26), दिनांक 10 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव।

Bhopal, the 10th June 2021

No. F A 3-07-2021-1-V (26) : In exercise of the powers conferred by Section 168A of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with Section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), in view of the spread of pandemic COVID-19 across many parts of India, the State Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies, as under,-

- (i) where, any time limit for completion or compliance of any action, by any authority or by any person, has been specified in, or prescribed or notified under the said Act, which falls during the period from the 15th day of April, 2021 to the 30th day of May, 2021, and where completion or compliance of such action has not been made within such time, then, the time limit for completion or compliance of such action, shall be extended upto the 31st day of May, 2021, including for the purposes of -

- (a) completion of any proceeding or passing of any order or issuance of any notice, intimation, notification, sanction or approval or such other action, by whatever name called, by any authority, commission or tribunal by whatever name called, under the provisions of the Acts stated above; or
- (b) filing of any appeal, reply or application or furnishing of any report, document, return, statement or such other record, by whatever name called, under the provisions of the Acts stated above;

but such extension of time shall not be applicable for the compliances of the provisions of the said Act, as mentioned below -

- (a) Chapter IV;
- (b) sub-section (3) of Section 10, Sections 25,27,31,37,47,50,69. 90,122, 129;
- (c) Section 39, except sub-section (3), (4) and (5);
- (d) Section 68, in so far as e-way bill is concerned; and
- (e) rules made under the provisions specified at clause (a) to (d) above;

Provided that where, any time limit for completion of any action, by any authority or by any person, specified in, or prescribed or notified under rule 9 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, falls during the period from the 1st day of May, 2021 to the 31st day, of May, 2021, and where completion of such action has not been made within such time, then, the time limit for completion of such action, shall be extended up to the 15th day of June, 2021,

- (ii) in cases where a notice has been issued for rejection of refund claim, in full or in part and where the time limit for issuance of order in terms of the provisions of sub-section (5), read with sub-section (7) of Section 54 of the said Act falls during the period from the 15th day of April, 2021 to the 30th day of May, 2021. in such cases the time limit for issuance of the said order shall be extended to fifteen days after the receipt of reply to the notice from the registered person or the 31st day of May, 2021 , whichever is later.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 15th day of April, 2021.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy, Secy.